



Two Day National Seminar on
Growth and Social Sector Development
in Uttar Pradesh Economy

6-7 April, 2017

SOUVENIR



Department of Economics
University of Lucknow
LUCKNOW 226007 (Uttar Pradesh)
INDIA

In Collaboration with
Indian Economic Association

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण दरिद्रता का वर्तमान स्वरूप

नीतू सिंह तोमर

आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन अनेक समस्याओं में दरिद्रता की समस्या सबसे अधिक ज्वलंत और जटिल है। यह समस्या समाज वैज्ञानिकों तथा शोधकर्ताओं का जितना ध्यान आकर्षित करती है उतना अन्य कोई समस्या नहीं करती है। दरिद्रों का उत्पीड़न भारतीय समाज की कोई नई समस्या नहीं है। भारतीय समाज के दरिद्र लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण के शिकार रहे हैं। साधारण जनता के लोग बाह्य शक्तियों जैसे जमींदार, राजनेताओं व्यापारियों एवं साहूकारों के द्वारा आर्थिक रूप से अनेकों रूपों में शोषित हो रहे हैं। उन्हें विभिन्न बेगार ली जा रही है। ऐसा व्यवहार राजकीय कर्मचारी भी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नए आर्थिक बल उन्हें अपना दास समझते हैं। व्यापारी एवं उद्योगपति उनसे बहुमूल्य भू-उपज एवं सम्पत्ति मिट्टी के भाव खरीद लेते हैं और उन्हें तड़क-भड़क वाली वस्तुयें ऊँचे दामों पर बेचते हैं।

आर्थिक शोषण का एक और तरीका भी है खाद्यान्न की समस्या से पीड़ित इन कमजोर साधनों जनों को प्रलोभन देकर ईट-भट्टों, कोल्ड स्टोर्स, मिलों, कृषि फार्मों, चाय के बगानों, खानों, होटलों, आवासों तथा स्कूलों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र से बाहर भी ले जाया जाता है। वहाँ मजदूरों के रूप में इनकी दशा दयनीय हो रही है क्योंकि न तो ये एक समय-सारणी में काम और औपचारिक ढंग से काम करने के आदी हैं और न मजदूरी के तौर-तरीकों से परिचित हैं। आधुनिक अर्थों में उनके कोई श्रम संघ भी नहीं हैं। इसलिए इन नए कार्य स्थलों पर उनसे जानवरों की तरह कार्य लिया जाता है और उनके स्वास्थ्य पर विकास की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। कानून भी इन आर्थिक रूप से शक्तिशाली धनी लोगों का ही साथ देता है।

भारत को स्वतन्त्रता हुए 69 वर्ष हो चुके हैं और देश के विकास के लिए यह कम समय नहीं है। देश वैज्ञानिक व तकनीकी सुदृढ़ता के साथ 21 वीं सदी के दूसरे दशक में गुजर रहा है। जहाँ एक ओर हम सब अपनी उपलब्धि देख कर हर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की एक तिहाई से अधिक अबादी को दरिद्र देख हमारा संर शर्म से झुक जाता है। वस्तुतः स्वतन्त्रता प्राप्त के इन लम्बे अंतराल के बाद भी व्यक्ति जीवन की आवश्यक जरूरतों यथा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की शिक्षा के अभाव में जीवन व्यतीत कर आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक और पारिवारिक स्वतन्त्रता के लिए आज भी संघर्षरत हैं। पुरानी रूढ़ियाँ, परम्परायें, अन्धविश्वास, सामंतवाद, पूंजीवाद, जटिलता और अंधाकानून पग-पग पर उनके पैरों में बंधनों की बेड़ियाँ डाले खड़े हैं। इस विषय में हमें विचार करना होगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जो दरिद्रों के विकास में बाधक हैं।

आजादी के उपरान्त संवैधानिक प्रावधानों में दरिद्रों के अधिकारों की गारण्टी दी गई है। आज भी दरिद्रों के उत्पीड़न में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। आज भी दरिद्रों का उत्पीड़न होता है, उनकी गुदड़ी भी छीनी जाती है, उनको बंधुआ बनाया जाता है, उनको जबरन

जर जेल में डाला जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका कल्याण लाभ हड़पा जाता है। इसी प्रकार भारतीय समाज दरिद्रों के उत्पीड़न का खुला नमूना है।

वस्तुतः दरिद्रता समस्त अपराधों एवं पापों की जननी है। यह मनुष्य को न केवल निराशा के तर्त में डुबो देती है वरन् उसमें धिनौनी हीनता को भी जन्म देती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पश्चिम के अनेक राष्ट्र असीम भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं वहीं आज दुनियाँ की 1.3 अरब दरिद्र जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है और दुनियाँ का हर तीसरा दरिद्र भारतीय है। इन दरिद्र भारतवासियों के पास न खाने के लिये पर्याप्त भोजन है, न पहनने हेतु पर्याप्त कपड़ा और न रहने के लिए उचित आवास-व्यवस्था। यही कारण है कि आज दरिद्रता हमारे देश की मुख्तम एवं ज्वलंत सामाजिक समस्या है।

एम.ए.पी.-एच.डी., समाजशास्त्र, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा : विकास, परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

जितेन्द्र सिंह गोयल*

जड़ अगर जिन्दा रही तो फिर हरा हो जाऊँगा कहते हैं कि नींव कमजोर हो तो उस पर भव्य इमारत खड़ा करना मुश्किल होता है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की न केवल नींव बल्कि उस पर खड़ी की गई दीवारें भी कमजोर हो गई हैं। इस नींव को जरूरतों को पूरा कर मजबूत करने की जरूरत है। बेसिक शिक्षा की व्यवस्थाएं अनदेखी के चलते बीमार दिखती हैं। मसलन शिक्षकों की कमी, अनुपयुक्त विद्यालय भवन, प्रयोगशालाओं की संसाधनहीनता, माइंड सेट के शिकार शिक्षक शिक्षिकाएं, परीक्षा में नकल, मूल्यांकन में अनदेखी और निजी कालेजों का व्यावसायिक दृष्टिकोण शिक्षा व्यवस्था की नींव में मट्टा डालने का काम कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दोबारा बनाया जाये, पाठ्यक्रम पर करके सीखने पर ज्यादा बल हो। छात्रों के फर्जी पंजीकरण पर लगे रोक, परीक्षा में नकल न हो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाये तभी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की दशा एवं दिशा सुधरेगी।

संकेत शब्द : प्राथमिक शिक्षा, पब्लिक स्कूल, पाठ्यक्रम।

* रिसर्च स्कॉलर, (शिक्षाशास्त्र विभाग) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, E-mail- jitendrago@gmail.com

उत्तर प्रदेश में आर्थिक संवृद्धि, रोजगार और गरीबी निवारण

अमितेन्द्र सिंह*

आर्थिक वृद्धि किस सीमा तक गरीबी निवारण में कमी लाने में मददगार हो सकती है, यह